राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि.

बनाम

डॉ राजा राम जयपुरिया एवं अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 4818 आदि)

जुलाई 01, 2013

खपी. सथासिवम और जगदीश सिंह खेहर, जे.जे.,

स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1986 रू

धारा 27 टेक्सटाइल उपक्रम का हिस्सा बनने वाली संपत्ति को गलत तरीके से रोकने की शिकायत - आयोजितरू डॉयपैक के मामले में, स्वदेशी हाउस के बंगला नंबर 2 को निहित करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा न तो विचार किया गया और न ही निर्णय लिया गया - डॉयपैक में स्पष्ट निर्णय, अस्वीकृति स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया बाद का आवेदन, सिविल कोर्ट से संपर्क करने का निर्देश, अधिनियम की धारा 27 के तहत शिकायत को खारिज करना और पीपी अधिनियम के तहत कार्यवाही, अपीलकर्ता के दावे और रुख के खिलाफ है, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा गया है -

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 एस.एस. 5 और 7.

केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास एफ विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 18 एए के तहत दिनांक 13.04.1978 की अधिसूचना द्वारा स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (एससीएमसीएल) के छह कपड़ा उपक्रमों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, जिसमें स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर भी शामिल है। अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, एनटीसी ने विभिन्न संपत्तियों पर कब्ज़ा और हिरासत ले ली एससीएमसीएल से संबंधित है जिसमें एक गेस्ट हाउस (बंगला नंबर 1) और परिसर का प्रशासनिक ब्लॉक (बंगला नंबर 3) शामिल है जिसे श्स्वदेशी हाउसश् के नाम से जाना जाता है। हालाँकि, श्स्वदेशी हाउसश् का बंगला नंबर 2 तत्कालीन निदेशक के भौतिक कब्जे में रहा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि. वी. डॉ. राजा 29 राम जयपुरिया एवं ओआरएस।

एससीएमसीएल (प्रतिवादी संख्या 1)। इसके बाद स्वदेशी कॉटन मिल्स में न्यायालय ने उक्त अधिग्रहण को अमान्य करार दिया, स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया और इसकी धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक कपड़ा उपक्रम और अधिकार, शीर्षक और हित उक्त कपड़ा

उपक्रम में एससीएमसीएल को स्थानांतरित कर दिया गया और केंद्र सरकार के पास निहित कर दिया गया। हस्तांतरित उपक्रमों को आगे स्थानांतरित कर एनटीसी में निहित कर दिया गया। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड, इस न्यायालय ने माना कि एससीएमसीएल का स्वामित्व और नियंत्रण एनटीसी के पास निहित है। यह भी माना गया कि बंगला नंबर 1 और स्वदेशी हाउस परिसर का प्रशासनिक ब्लॉक भी केंद्र सरकार में निहित है। बंगला नंबर 2 के संबंध में अपीलकर्ता के दावे को अदालतों का समर्थन नहीं मिला। स्वदेशी अधिनियम की धारा 27 और एस.एस. से उत्पन्न त्वरित कार्यवाही में। सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 5 और 7, अपीलकर्ता द्वारा बंगला नंबर पर कब्जे का दावा करते हुए शुरू की गई। 2, यह अपने मामले में सफल नहीं हुआ और अंततः, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेशों द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 डोयपैक में फैसले के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि मुद्दा यह है कि क्या बंगला। स्वदेशी हाउस का क्रमांक 2 अपीलकर्ता में निहित है या नहीं, उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा इस पर न तो विचार किया गया और न ही निर्णय लिया गया। अपीलकर्ता ने इस वादे पर बार-बार विभिन्न कार्यवाही दायर की कि बंगला नंबर 2 स्वदेशी हाउस का

हिस्सा है, लेकिन सभी प्रयासों में विफल रहा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सारी कार्यवाही अपीलकर्ता के विरुद्ध हुई। पैरा 9 और 15, 40-बी-सी; 43-एफ-जी,

डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य

1988 (2) एससीआर 962 = (1988) 2 एससीसी 299 संदर्भित। 1.2 अलग-अलग आदेश और निर्णय अलग-अलग

सर्वाेच्च न्यायालय की रिपोर्ट 2013, 7 एस.सी.आर

अदालतों ने अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता द्वारा तत्काल कार्यवाही में उसी मुद्दे को फिर से उठाने की मांग की गई। डॉयपैक में इस न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के मद्देनजर, स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर बाद के आवेदन की अस्वीकृति, सिविल अदालत से संपर्क करने का निर्देश, पीपी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना जो बर्खास्तगी में समाप्त हुआ, धारा 27 के तहत शिकायत को खारिज करना। विभिन्न अदालतों द्वारा स्वदेशी अधिनियम का उल्लंघन निस्संदेह अपीलकर्ता के दावे और रुख के खिलाफ जाता है। पैरा 16, 43-एच; 44-ए-बी,

1.4 ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश और साथ ही उच्च न्यायालय को बरकरार रखा गया है. पैरा 17, 44-डी,

केस कानून संदर्भः

1988 (2) एससीआर 962 करने के लिए भेजा 3 के लिए

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की सिविल अपील संख्या 4818.

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या 1994 का 25090 विविध मामलों में निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.11.2005 से।

साथ

सीए 2013 की संख्या 4819।

इंदिरा जयसिंह, एएसजी, दुष्यन्त दवे, के.वी. विश्वनाथन, संजय घोष, कौस्तुभ अंशुराज। अनिता शेनॉय. शब्याशाची पात्रा, संजीव के. कपूर, खेतान एंड कंपनी, रोहित कुमार सिंह, मेहुल एम. गुप्ता, गौतम नारायण उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

पी. सदाशिवम, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. ये अपीलें अंतिम निर्णय के विरुद्ध निर्देशित हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि. वी डॉ। राजा राम जयपुरिया एवं ओआरएस। पी. सदाशिवम, जे.और विविध मामलों में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2005। रिट याचिका संख्या 25090 वर्ष 1994 और 30122 वर्ष 1996 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने नेशनल

टेक्सटाइल कॉर्पाेरेशन (यूपी) लिमिटेड - यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

2006 की एसएलपी (सिविल) संख्या 4706

3. संक्षिप्त तथ्यः

(ए) वर्ष 1921 में, स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (एससीएमसीएल) को एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और 1923 में एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था जो कपड़ा मिलों के संचालन और प्रबंधन की गतिविधि के व्यवसाय में लगी हुई थी। एससीएमसीएल ने सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश में संपत्ति का अधिग्रहण किया, जिस पर एक एकीकृत परिसर का निर्माण किया गया जिसे श्स्वदेशी हाउसश् के नाम से जाना जाता है। उक्त सदन में तीन इमारतें शामिल थीं, बंगला नंबर 1 जिसका उपयोग 1971 से पहले एससीएमसीएल के पंजीकृत कार्यालय के रूप में किया जाता था और 1971 के बाद इसका उपयोग निदेशक मंडल की सामान्य बैठकों और गेस्ट हाउस, बंगले के रूप में भी किया जाता था। नंबर 2 एससीएमसीएल के प्रबंध निदेशक के भौतिक कब्जे में था और बंगला नंबर 3 एससीएमसीएल का प्रशासनिक ब्लॉक था।

(बी) केंद्र सरकार ने, औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 18 एए के तहत दिनांक 13.04.1978 की अधिसूचना के

माध्यम से, स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर और नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पाेरेशन लिमिटेड सहित एससीएमसीएल के छह कपड़ा उपक्रमों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। , नई दिल्ली (एनटीसी), एक सरकारी उपक्रम, को उक्त अधिग्रहण के तहत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, एनटीसी ने गेस्ट हाउस और प्रशासनिक ब्लॉक सहित एससीएमसीएल से संबंधित विभिन्न संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। हालाँकि, बंगला नंबर 2 एससीएमसीएल के तत्कालीन निदेशक (यहां प्रतिवादी नंबर 1) डॉ. राजा राम जयपुरिया के भौतिक कब्जे में रहा।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2013, 7 एस.सी.आर. (सी) अधिग्रहण के दिनांक 13.04.1978 के आदेश से व्यथित होकर, एससीएमसीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 1978 की रिट याचिका संख्या 408 दायर की। उच्च न्यायालय में, दिनांक 04.05.1978 के आदेश के तहत, पार्टियों के बीच एक कामकाजी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 को आवासीय बंगले का भौतिक कब्जा इस शर्त पर जारी रखने की अनुमति दी गई थी कि उसका निपटान नहीं किया जाएगा। या किसी भी तरह से किसी बाहरी व्यक्ति से अलग हो गया हो। अंततः, दिनांक 01.05.1979 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.04.1978 की अधिसूचना को बरकरार रखा, लेकिन कुछ संपत्तियों को उसी के दायरे से बाहर रखा गया,

जिसमें श्स्वदेशी हाउस और श्झाड़ीश् - एससीएमसीएल के सचिव का निवास शामिल था।

(डी) अधिग्रहण के आदेश की वैधता और वैधानिकता के संबंध में उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, स्वदेशी कॉटन मिल्स, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन और यूनियन ऑफ इंडिया ने इस न्यायालय के समक्ष क्रमशः 1979 की सिविल अपील संख्या 1629, 1857 और 2087 को प्राथमिकता दी। इस न्यायालय ने स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ (1981) 1 एससीसी 664 में दिनांक 13.01.1981 के फैसले के तहत उक्त अधिग्रहण को इस आधार पर अमान्य ठहराया कि अधिग्रहण से पहले एससीएमसीएल को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

(ई) 19.04.1986 को, केंद्र सरकार ने स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1986 प्रख्यापित किया। इसके बाद, 30.05.1986 को, उक्त अध्यादेश को स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (अधिग्रहण) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1986 (संक्षेप में श्स्वदेशी अधिनियमश्)। स्वदेशी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक कपड़ा उपक्रम और उक्त कपड़ा उपक्रम में एससीएमसीएल के अधिकार, शीर्षक और हित केंद्र सरकार के पास स्थानांतरित और निहित हो गए। हस्तांतरित उपक्रमों को आगे स्थानांतरित कर एनटीसी में निहित कर दिया गया।

एससीएमसीएल के उपक्रमों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप पार्टियों द्वारा कई कार्यवाही शुरू की गईं।

(एफ) स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड (एसपीएल) के अल्पसंख्यक शेयरधारक मुकेश भसीन ने एक सिविल सूट दायर किया।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि. वी डॉ। राजा 33 राम जयपुरिया एवं ओआरएस। ख्पी। सदाशिवम, जे.,.नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 1987 का 506 इस आधार पर एससीएमसीएल के खिलाफ एक घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि सभी निवेश और संपत्ति एनटीसी के पास हैं जो स्वदेशी के लागू होने के बाद संपत्ति का असली मालिक है। कार्यवाही करना। उक्त मुकदमे में, उन्होंने एससीएमसीएल और स्वदेशी बी माइनिंग (एससीएमसीएल की सहायक कंपनी) को स्वदेशी हाउस के मालिकों के रूप में मान्यता देने से एसपीएल के खिलाफ निषेधाज्ञा की भी मांग की।

(जी) स्वदेशी कॉटन मिल्स और एससीएमसीएल ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) के समक्ष 1987 की रिट याचिका संख्या 2214 को प्राथमिकता दी, जिसमें दावा किया गया कि एसपीएल और स्वदेशी खनन और अन्य ष्बहिष्कृत संपत्तियोंष् में एससीएमसीएल द्वारा रखे गए इक्विटी शेयर स्वदेशी अधिनियम के दायरे और दायरे से मुक्त घोषित किया जाना चाहिए। (एच) 1987 के उपरोक्त सिविल सूट

संख्या 506 और 1987 की रिट याचिका संख्या 2214 को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और क्रमशः 1987 के स्थानांतरण मामले संख्या 14 और 13 के रूप में क्रमांकित किया गया। इस न्यायालय ने मेसर्स डोयपैक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में दिनांक 12.02.1988 के फैसले के तहत। लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1988) 2 एससीसी 299, ने 1987 के ट्रांसफर केस नंबर 14 को अनुमति दी और 1987 के ट्रांसफर केस नंबर 13 को खारिज कर दिया और माना कि एससीएमसीएल का स्वामित्व और नियंत्रण एनटीसी के पास है। यह भी माना गया कि बंगला नंबर 1 और प्रशासनिक ब्लॉक, सिविल लाइन्स, कानपुर भी केंद्र सरकार में निहित हैं।

(आई) चूंकि एससीएमसीएल स्वदेशी हाउस के बंगला नंबर 2 का कब्ज़ा सौंपने में विफल रही, एनटीसी ने सिविल विविध दायर किया। 1987 के ट्रांसफर केस नंबर 13 में याचिका नंबर 26004, 1988 में एससीएमसीएल को बंगला नंबर 2 का खाली कब्जा सौंपने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। दिनांक 03.08.1989 के आदेश के तहत, याचिका को बिना किसी आदेश के स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया था। उपयुक्त न्यायालय. उक्त आदेश के मद्देनजर, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन (यू.पी.) लिमिटेड (यहां अपीलकर्ता), जो एनटीसी का उत्तराधिकारी था, ने अदालत में प्रतिवादी और अन्य के खिलाफ 1991 की

आपराधिक शिकायत संख्या 1661 दर्ज की। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कोतवाली, कानपुर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 2013, 7 एस.सी.आर.

उक्त बंगले पर कब्जे के लिए स्वदेशी अधिनियम की धारा 27 के तहत ए. दिनांक 18.02.1993 के आदेश के तहत, डोयपैक (सुप्रा) में दिए गए फैसले के मद्देनजर उक्त शिकायत खारिज कर दी गई कि केवल बंगला नंबर 1 और प्रशासनिक ब्लॉक केंद्र सरकार के पास है।

दिनांक 18.02.1993 के आदेश से व्यथित होकर, एनटीसी ने सत्र न्यायाधीश, कानपुर के समक्ष 1993 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 86 दायर किया, जिसे दिनांक 30.10.1993 के आदेश के तहत यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि एनटीसी संदेह से परे साबित करने में विफल रही। उक्त बंगला दिनांक 03.08.1989 के आदेश के अनुसार उचित न्यायालय में जाने के निर्देश के साथ केंद्र सरकार के पास निहित है।

(के) इससे व्यथित होकर, एनटीसी ने 1994 की रिट याचिका संख्या 25090 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बीच, एनटीसी ने डॉयपैक (सुप्रा) में फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस न्यायालय के समक्ष 1987 के ट्रांसफर केस नंबर 14 में 2005 की अवमानना याचिका संख्या 75 दायर की, लेकिन इसे दिनांक 03.02 2006 के आदेश के आधार पर खारिज कर दिया गया। तत्काल कार्यवाही के बारे

में खुलासा करने में चूक। आदेश ई दिनांक 25.11.2005 के तहत उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।

(एल) उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

2006 की एसएलपी (सिविल) संख्या 4773

(एम) 26.10.1989 को, एनटीसी ने सार्वजनिक परिसर (जी अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (संक्षेप में श्पीपी अधिनियम) की धारा 5 और 7 के तहत प्रतिवादी को उक्त स्थान से बेदखल करने के लिए एक आवेदन दायर किया। बंगला इस आधार पर कि डोयपैक (सुप्रा) में, यह पहले ही माना जा चुका है कि स्वदेशी हाउस (जिसमें बंगला नंबर 2 भी शामिल है) एनटीसी के साथ निहित है और यहां प्रतिवादी के शीर्षक एच के बारे में कोई सवाल नहीं है। के लंबित रहने के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि. वी डॉ। राजा राम जयपुरिया एवं ओआरएस। ख्पी। सदाशिवम, जे.,.

संपत्ति अधिकारी, श्री राजाराम जयपुरिया (यहाँ प्रतिवादी नंबर 2) के समक्ष कार्यवाही ने बंगला नंबर 2 से कुछ कीमती सामान हटा दिया। एनटीसी ने संपत्ति अधिकारी के समक्ष प्रतिवादियों को रोकने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे आदेश दिनांक द्वारा अनुमति दी गई थी। 02.05.1993.

(एन) व्यथित होकर, मेसर्स गणेश सिंथेटिक्स प्रा. लिमिटेड (यहां प्रतिवादी संख्या 16), एससीएमसीएल की एक संबंधित इकाई, ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1993 की एक रिट याचिका संख्या 16091 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.05.1993 के आदेश द्वारा, प्रतिवादियों को बंगला नंबर 2 में रखे किसी भी सामान को हटाने से रोक दिया। दिनांक 05.08.1994 के आदेश के अनुसार, संपदा अधिकारी ने एससीएमसीएल द्वारा दायर सभी प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसमें उत्तरदाताओं ने जिला न्यायालय, कानपुर के समक्ष पीपी अधिनियम की धारा 9 के तहत 1994 की अपील संख्या 228 को प्राथमिकता दी।

(ओ) दिनांक 01.05.1996 के आदेश के तहत, उपरोक्त अपील को यह कहते हुए अनुमति दी गई थी कि डॉयपैक (सुप्रा) ने बंगला नंबर 2 से संबंधित मुद्दे को संबोधित नहीं किया था। व्यथित होने के कारण, एनटीसी ने 1996 की रिट याचिका संख्या 30122 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.11.2005 के आदेश द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

(पी) उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

4. सुश्री इंदिरा जयसिंह, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री दुष्यंत दवे, प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री के.वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री गौतम नारायण, क्रमशः नए पक्षकारों - कानपुर बिल्डर्स और कपड़ा मंत्रालय के लिए विद्वान वकील थे।

5. अपीलकर्ता-एनटीसी का यह निश्चित मामला है स्वदेशी हाउस हमेशा से था और इसमें शामिल है एकीकृत परिसर में तीन इमारतें शामिल हैं, अर्थात.

सर्वोच्च न्यायाय की रिपोर्ट 2013, 7 एस.सी.आर.

बंगला नंबर 2 (निदेशकों के निजी निवास के रूप में उपयोग किया जाता है), बंगला नंबर 1 (कंपनी के गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग किया जाता है) और नौकरों के क्वार्टर और आसन्न भूमि के अलावा एक प्रशासनिक ब्लाॅक और स्वदेशी अधिनियम की धारा 3 के कारण, प्रत्येक कपड़ा उपक्रम और उक्त कपड़ज़ उपक्रम में एससीएमसीएल का अधिकार, शीर्षक और हित केंद्र सरकार के साथ स्थानांतरित और निहित हो गया। एससीएमसीएल के स्वामित्व की चिंता है।

6. दूसरी ओर, यह प्रतिवादियों का मामला है कि एससीएमसीएल, कानपुर की संपत्ति, जो केंद्र सरकार के पास है, उसमें बंगला नंबर 2 शामिल नहीं है क्योकि वह हमेशा एससीएमसीएल का निर्माण किया गया

है वह वर्ष 1921 में खरीदी गई थी और भवन इसके तुरंत बाद इसका निर्माण किया गया। उक्त जमीन व मकान थे द्वारा अर्जित लाभ से क्रय/निर्माण नहीं किया गया एससीएमसीएल, कानपुर लेकिन शेयरधारकों की निधि से व्यवस्था की गई अन्यथा की गई अन्यथा। उनका यह भी दावा है कि उक्त भूमि, जैसा कि निर्णय लिया गया था, बंगला नंबर 2 कभी भी अपीलकर्ता में निहित नहीं था डोयपैक (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा। यह हमारे संभान में भी लाया गया है उत्तरदाताओं द्वारा बंगला नं. 1 एवं 2 रहा है कानपुर नगर पालिका द्वारा अब तक अलग परिसर के रूप में दर्ज किया गया जब से उक्त दो बंगलों का निर्माण हुआ है। एफ ने यह भी बताया कि वर्तमान में बंगला नंबर 1 का नंबर परिसर नंबर 16/15 है और बंगला नंबर 2 का नंबर परिसर नंबर 16/14, सिविल लाइन्स, कानपुर है और दोनों अलग-अलग परिसर है जिनकी अलग-अलग सीमाएं है।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्वदेशी अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख करना प्रासंगिक हैः

(प) स्वेदशी अधिनियम की धारा 2 (सी) में, एससीएमसीएल का एक पंजीकृत कार्यालय '' स्वेदशी हाउस'' में होने का संदर्भ है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि. वी. डॉ. राजा राम जयपुरिया एवं ओआरएस। पी। सदाशिवम, जे., (पप)

(पप) अभिव्यक्ति ''कपड़ा उपक्रम'' को परिभाषित किया गया है धारा 2(के) में निम्नलिखित छह कपड़ा उपक्रमों का मतलब है एससीएमसीएलरू

(ए) स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर;

(बी) स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडिचेरीरू

(सी) स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी;

(क) स्वदेशी काॅटन मिल्स, माउनाथ भंजन ,

(ई) उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर;

(एफ) रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स,रायबरेली;

(पपप) स्वदेशी अधिनियम की धारा 3 एससीएमसीएल के अधिकार, शीर्षक और हित को ष्प्रत्येक ऐसे कपड़ा डी उपक्रमष् को केंद्र सरकार और उसके बाद राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एनटीसी) में स्थानांतरित और निहित करती है।

(पअ) स्वदेशी अधिनियम की धारा 4 ''निहित'' के प्रभाव को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

(1) धारा 3 में निर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों में सभी संपत्तियां, अधिकार, पट्टा-धारण, शक्तियां, प्राधिकरण और विशेषाधिकार और भूमि, भवन, कार्यशालाएं, भंडार, उपकरण सहित सभी चल और अचल संपत्ति शामिल मानी जाएंगी। मशीनरी और उपकरण, एफ नकद शेष, हाथ पर नकदी,

आरक्षित निधि, कपड़ा उपक्रमों से संबंधित निवेश और बही ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित, जो स्वामित्व में नियत दिन से ठीक पहले थे, उक्त उपक्रमों के संबंध में जी कंपनी का कब्ज़ा, शक्ति या नियंत्रण, चाहे वह भारत के भीतर हो या बाहर, और सभी खातों की किताबें, रजिस्टर और उनसे संबंधित किसी भी प्रकृति के सभी अन्य दस्तावेज़।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2013, 7 एस.सी.आर.

(अ) स्वदेशी अधिनियम की धारा 8 प्रदान करती है एससीएमसीएल को 24,32,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

(अप) धारा 27 निम्नानुसार दंड से संबंधित हैः

27. दंड कोई भी व्यक्ति जो:-

(ए) किसी भी कपड़ा उपक्रम का हिस्सा बनने वाली किसी भी संपत्ति को अपने कब्जे, हिरासत या नियंत्रण में रखते हुए, ऐसी संपत्ति को राष्ट्रीय कपड़ा निगम से गलत तरीके से रोक लेता है; या

(बी) किसी भी कपड़ा उपक्रम का हिस्सा बनने वाली किसी भी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्ज़ा प्राप्त करता है, या बनाए रखता है; या दो साल तक की कैद और दस हजार रुपये तक के

जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दो साल तक की कैद और दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

8. विद्वान एएसजी ने हमारे ध्यान में लाया है कि एससीएमसीएल के कपड़ा उपक्रमों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप पार्टियों द्वारा कई कार्यवाही शुरू की गई थीं। दो महत्वपूर्ण कार्यवाही हैंः

(1) 26.02.1987 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकेश भसीन द्वारा एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था, उक्त मुकदमे के पैराग्राफ 3 (गपग) में, अपीलकर्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कींः

(गपग) स्वदेशी हाउस कानपुर उपक्रम का एक अभिन्न अंग है और इसमें भूमि और भवन का पर्याप्त क्षेत्र शामिल है। वादी का यथोचित और प्रामाणिक मानना है कि उक्त सदन 1921 में प्रतिवादी नंबर 3 के लाभ के लिए कपड़ा उपक्रम के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था और

39

राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि. वी. डॉ. राजा राम जयपुरिया एवं अन्य। पी। सदाशिवम, जे.,

अपने व्यवसाय का उपयोग, जिसमें उस समय केवल कानपुर टेक्सटाइल उपक्रम शामिल था''।

उक्त मुकदमे में, निम्नलिखित प्रार्थना की मांग की गई थीः

(ए) कि प्रतिवादी नंबर 1, प्रतिवादी नंबर 3 के पास प्रतिवादी नंबर 2 के 10 लाख इक्विटी शेयरों और प्रतिवादी नंबर 2 में प्रतिवादी नंबर 4 के पास 17,18,000/- इक्विटी शेयरों का असली मालिक है और कानपुर में स्वदेशी हाउस और उससे जुड़े सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज प्रतिवादी संख्या 3 के कपड़ा उपक्रम से संबंधित संपत्ति और निवेश हैं और वे 1.4.1985 से प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 में निहित हैं। स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री द्वारा उनके साथ किसी भी तरह से व्यवहार करने से रोका जा सकता है।

(बी) प्रतिवादी नंबर 2 को भी उपरोक्त शेयरों और स्वदेशी हाउस के मालिकों के रूप में प्रतिवादी नंबर 3 और 4 को मान्यता देने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना चाहिए।

(2) ''दूसरी स्वदेशी द्वारा स्थापित एक याचिका थी खनन और विनिर्माण कंपनी लिमिटेड

(''एसएमएमसीएल''), की सहायक कंपनी। उक्त में याचिका, सिविल डब्ल्यू.पी. होने के नाते 1987 का क्रमांक 2214 के उच्च न्यायालय में 03.04.1987 को स्थापित किया गया इलाहाबाद (लखनऊ बेंच), एससीएमसीएल थी।

याचिकाकर्ता संख्या 2। 1987 के उपरोक्त सिविल सूट संख्या 506 और 1987 की रिट याचिका संख्या 2214 को इस न्यायालय में

स्थानांतरित कर दिया गया था और क्रमशः 1987 के स्थानांतरण मामले संख्या 14 और 13 के रूप में क्रमांकित किया गया था। इस न्यायालय ने, दिनांक 12.02 के फैसले के तहत। 1988 में डोयपैक (सुप्रा) में 1987 के ट्रांसफर केस नंबर 14 की अनुमति दी गई और 1987 के ट्रांसफर केस नंबर 13 को खारिज कर दिया गया।

9. दोनों पक्षों ने डॉयपैक (सुप्रा) के विभिन्न पैराग्राफों का विस्तार से विज्ञापन किया। वास्तव में, डोयपैक (सुप्रा) पर निर्भरता के आधार पर, एएसजे ने यह प्रस्तुत किया

सर्वाेच्च न्यायालय की रिपोर्ट 2013, 7 एस.सी.आर.

स्वदेशी हाउस, कानपुर का बंगला नंबर 2 उनके पास निहित है। दोनों पक्षों के दावे और दावे के आलोक में हमारे पास है डॉयपैक (सुप्रा) में पूरे फैसले का अध्ययन किया गया। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता बी द्वारा शुरू की गई पिछली कानूनी कार्यवाही में विभिन्न अदालतों द्वारा उक्त निर्णय की जांच की गई थी और इस अदालत सहित ऐसी सभी कार्यवाही को अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया था। डोयपैक (सुप्रा) में फैसले के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि इस मुद्दे पर कि स्वदेशी हाउस का बंगला नंबर 2 अपीलकर्ता को निहित है या नहीं, उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा न तो विचार किया गया और न ही निर्णय

लिया गया। यह के पहले पैराग्राफ को पढ़ने से स्पष्ट है निर्णय स्वयं जो निम्नानुसार पढ़ता है।

1. इन सभी मामलों में जो विचाराधीन है वह कानून का एक सामान्य प्रश्न है, अर्थात्, क्या दोनों कंपनियों में इक्विटी शेयर यानी स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड में 10,00,000 शेयर और स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में 17,18,344 शेयर रखे गए हैं। स्वदेशी कॉटन मिल्स द्वारा, स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1986 (इसके बाद ष्उक्त अधिनियमष् के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित है। दूसरा। सहायक प्रश्न यह है कि क्या अचल संपत्तियाँ, अर्थात् बंगला नंबर 1 और प्रशासनिक ब्लॉक, सिविल लाइन्स, कानपुर भी सरकार में निहित हो गई हैं। झाड़ीदार संपत्ति के रूप में जानी जाने वाली एक और संपत्ति के बारे में सवाल अभी भी है कि क्या इसे ले लिया गया है या नहीं और तर्क दिया जा सकता है और यह इस निर्णय में शामिल नहीं है।

10. उपरोक्त से, वे प्रश्न जो बने डॉयपैक (सुप्रा) की विषय वस्तु इस प्रकार थीः

(ए) क्या दोनों कंपनियों में इक्विटी शेयर, यानी...स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड में 10,00,000 शेयर और स्वदेशी कॉटन मिल्स के पास स्वदेशी

माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में 17,18,344 शेयर, केंद्र सरकार के अधीन हैं स्वदेशी की धारा 3

41

राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि. वी डॉ। राजा राम जयपुरिया एवं ओआरएस। पी। सदाशिवम, जे.जे

कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (समझौते का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1986 (इसके बाद इसे ''अधिनियम''के रूप में जाना जाएगा)।

(बी) क्या अचल संपत्तियां, अर्थात् बंगला नंबर 1 और प्रशासनिक ब्लॉक, सिविल लाइन्स, कानपुर भी सरकार में निहित हैं''।

विस्तृत तर्क के बाद, उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ संख्या 69 और 70 में निम्नानुसार दिया गयाः

69. इसलिए, हम दोहराते हैं कि शेयर केंद्र सरकार में निहित हैं। तदनुसार, विचाराधीन शेयर एनटीसी में निहित हैं और उक्त 34 प्रतिशत शेयर पर उसका अधिकार है शेयरधारिता का प्रतिशत।

70. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में हम मानते हैं कि स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड में 10,00,000 शेयर और स्वदेशी कॉटन मिल्स द्वारा स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में 17,18,344 शेयर धारा 3 और 4 के तहत केंद्र सरकार में निहित हैं। अधिनियम।

71. हमारी यह भी राय है कि के मद्देनज़र प्रयुक्त भाषा का आयाम, अचल

संपत्तियां, अर्थात् बंगला नंबर 1 और प्रशासनिक ब्लॉक, सिविल लाइन्स, कानपुर को भी निहित किया गया है एनटीसी में।

11. डोयपैक (सुप्रा) में फैसले को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वदेशी हाउस, कानपुर के बंगला नंबर 2 को निहित करने के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा उक्त फैसले में विचार नहीं किया गया था। अतरू अपीलार्थी का वही तर्क अस्वीकार किये जाने योग्य है

12. चूंकि एससीएमसीएल स्वदेशी हाउस के बंगला नंबर 2 का कब्ज़ा सौंपने में विफल रही, एनटीसी ने सिविल विविध दायर किया। याचिका संख्या 26004/1988 में ट्रांसफर केस संख्या 13/1987 में एससीएमसीएल को रिक्त पद सौंपने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

42

सर्वाेच्च न्यायालय की रिपोर्ट 2013, 7 एस.सी.आर.

बंगला नंबर 2 का कब्ज़ा। उक्त आवेदन का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 03.08.1989 को किया गया था जो इस प्रकार हैः

1988 का सीएमपी नंबर 26004 रू इस पर कोई आदेश नहीं होगा सीएमपी. इससे पार्टियों के स्थानांतरित होने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कानून के अनुसार उपयुक्त अदालतें।

उपरोक्त आदेश से, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने स्वदेशी हाउस के बंगला नंबर 2 से संबंधित मुद्दे का फैसला नहीं किया और अपीलकर्ता के लिए उपयुक्त के समक्ष जाकर उक्त बंगले के संबंध में स्वामित्व के प्रश्न पर आंदोलन करने का अधिकार खुला छोड़ दिया था। सी अदालत कानून के अनुसार. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा कभी भी ऐसी कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

13. यह बताना उपयोगी होगा कि सिविल की बर्खास्तगी के बावजूद विविध. 1988 की याचिका संख्या 26004 टी.सी. में 1987 की संख्या 13 में, डी अपीलकर्ता ने डोयपैक (सुप्रा) में फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 1987 के स्थानांतरण मामले संख्या 14 में 2005 की अवमानना याचिका संख्या 75 दायर करके फिर से इस न्यायालय के समक्ष कदम रखा। उक्त अवमानना याचिका में अपीलकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि अवमाननाकर्ताओं ने बंगला नंबर 2 को कानपुर बिल्डर्स लिमिटेड को बेच दिया है, इसलिए उन्होंने डॉयपैक (सुप्रा) में फैसले का उल्लंघन किया है और इसलिए, वे दंडित होने के लिए उत्तरदायी हैं। अवमानना। उक्त अवमाननायाचिका में उक्त कानपुर बिल्डर्स लिमिटेड के निदेशक को भी अवमाननाकर्ता संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया था। दिनांक 03.02.2006 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उक्त अवमाननायाचिका को खारिज कर दिया। मुकदमेबाजी के कई दौर के बाद, जैसा कि पैराग्राफ (उपरोक्त) में चर्चा की गई है, अपीलकर्ता ने

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 1994 की रिट याचिका संख्या 25090 दायर की। दिनांक 25.11.2005 के निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 1986 के अधिनियम 30 की धारा 27 के तहत एक शिकायत केवल अपीलकर्ता द्वारा दायर की जा सकती थी यदि संपत्ति उनमें निहित थी. इसे उच्च न्यायालय द्वारा आगे रखा गया था वह कि अधिनियम 30 की धारा 27 के तहत एक शिकायत 1986 केवल याचिकाकर्ता द्वारा ही दायर किया जा सकता था यदि शीर्षक

43

राष्ट्रीय कपड़ा निगम. (यूपी) लि. वी डॉ। राजा राम जयपुरिया एवं ओआरएस। पी। सदाशिवम, जे.,.

विवादित संपत्ति का मामला स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में था। नीचे दी गई दोनों अदालतों ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सही आकलन किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनके पक्ष में कोई स्पष्ट शीर्षक नहीं होने के कारण धारा 27 के तहत शिकायत गलत समझी गई थी और इसलिए इसे खारिज करना सही है।

14. उपरोक्त कार्यवाही के अलावा, अपीलकर्ता ने पीपी अधिनियम की धारा 5 और 7 के तहत उनके निष्कासन के लिए आगे की कार्यवाही शुरू की। इसी तरह, मुकदमेबाजी के दौर के बाद, यहां अपीलकर्ता का दावा

खारिज कर दिया गया और अंततः अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 की रिट याचिका संख्या 30122 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.11.2005 के आदेश द्वारा इसे भी खारिज कर दिया और निम्नानुसार मानाः

विद्वान जिला न्यायाधीश ने भी सही निष्कर्ष निकाला है कि बंगला नंबर 2 याचिकाकर्ता के पास नहीं है। यह, विद्वान न्यायाधीश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित निर्णय के आधार पर कहा है डॉयपैक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एआईआर 1988 एससी 782 के मामले में, जिसमें बंगला नंबर 1 और प्रशासनिक ब्लॉक के एकमात्र निहितार्थ को बरकरार रखा गया है। याचिकाकर्ता के लिए यह खुला छोड़ दिया गया था कि वह अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है। बंगला नंबर 2। याचिकाकर्ता द्वारा कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के पक्ष में स्वामित्व की घोषणा करने वाला कोई आदेश नहीं है।

15. उपरोक्त सभी आवेदनों/याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पैराग्राफ (सुप्रा) में उल्लिखित है, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने इस आधार पर बार-बार विभिन्न कार्यवाही दायर की है कि बंगला नंबर 2 स्वदेशी हाउस का हिस्सा है। लेकिन सभी प्रयासों में

असफल रहे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यहां सारी कार्यवाही अपीलकर्ता के खिलाफ हुई।

16. उपरोक्त सभी विवरण, विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न आदेशों और निर्णयों ने अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया और अब अपीलकर्ता द्वारा उसी मुद्दे को फिर से उठाने की मांग की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 2013, 7 एस.सी.आर.

वर्तमान कार्यवाही में ए. हम इस बात से संतुष्ट हैं कि डोयपैक (सुप्रा) में इस न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के मद्देनजर, स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर बाद के आवेदन की अस्वीकृति, सिविल कोर्ट से संपर्क करने का निर्देश, पीपी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना जो बर्खास्तगी में समाप्त हुई, स्वदेशी अधिनियम की धारा 27 के तहत शिकायत को खारिज करने का फैसला विभिन्न अदालतों द्वारा पारित किया गया, जो निस्संदेह अपीलकर्ता के दावे और रुख के खिलाफ जाता है। यह हमारे पास भी लाया जाता है नए पक्षकारों द्वारा नोटिस जो उन्होंने खरीदा था उक्त संपत्ति को प्रामाणिक तरीके से साफ शीर्षक के साथ संपत्ति एससीएमसीएल में निहित है, इसलिए, वे इसके हकदार हैं जो उसी। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमने कोई भी बात व्यक्त नहीं की है. उक्त मुद्दे के बारे में।

17. उपरोक्त के मद्देनजर, हम ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से पूरी तरह सहमत हैं, परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा। डी

आर.पी.

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक कल्पना पारीक (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।